

“सफलता की खुशी मनाना
अच्छ है पर,
उससे जरूरी है अपनी
असफलता से सीख लेना !

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 01, अंक 229, नई दिल्ली

मंगलवार, 31 अक्टूबर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

दिल्ली ने एनसीआर क्षेत्र में पुरानी डीजल बसों के खिलाफ किया जंग का एलान, जानें इसकी वजह

संजय बाटला, सम्पादक

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर क्षेत्र में प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चलने वाली पुरानी डीजल बसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एनयूआई) लगातार खराब होने के साथ, वाहन उत्सर्जन को मुख्य योगदान कारकों में से एक माना जाता है। यहां तक कि प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों में चलने वाली डीजल बसों की ओर इशारा कर रही है।

दिल्ली का AQI 400 से ज्यादा हो गया है जिसे 'खतरनाक' माना जाता है और यह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। आने वाले दिनों में गिरते तापमान, हवा की कम रफ्तार और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की संभावना बढ़ने से जहरीली हवा के और भी जहरीली होने की संभावना है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अब तीन पड़ोसी राज्यों में डीजल से चलने वाली प्रदूषण फैलाने वाली बसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

राय ने इस बात पर रोशनी डाली है कि जहां दिल्ली में सार्वजनिक बसें सीएनजी पर चलती हैं और प्रदेश के अमृत कलश से मिली व चावल को कर्तव्य पथ पर बड़े कलश में डालेंगे।

कर्तव्य पथ पर अमृत कलश यात्रा का समापन आज, पटेल जयंती पर होगा बड़ा आयोजन, यातायात परिवर्तन

नई दिल्ली। कर्तव्य पथ पर मेरी माटी-मेरा देश कार्यक्रम के तहत सोमवार को अमृत कलश यात्रा का समापन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी मार्च करेंगे। आयोजन स्थल पर राज्य के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियां होंगी जिसमें आर्य और प्रदेश के अमृत कलश से मिली व चावल को कर्तव्य पथ पर बड़े कलश में डालेंगे।

पटेल जयंती : दो दिन तक रूट देखकर ही निकलें

सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर सोमवार और मंगलवार को विजय चौक पर मेगा इवेंट मेरी माटी मेरा देश-अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। समारोह में देश के गणमान्य लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को देखते हुए यातायात पुलिस ने आयोजन स्थल के आसपास से गुजरने वाले रास्तों से वाहन चालकों को बचने की सलाह दी है। यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आवश्यकता पड़ने पर विजय चौक के आसपास वाहनों को वैकल्पिक रास्तों पर भेजा जा सकता है।

टैपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम-डीएल-0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042



राज्यों में डीजल से चलने वाली बसों की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कहा, रवाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन दिल्ली के वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि दिल्ली में बसें सिर्फ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बसें बीएस III और बीएस IV वाहन हैं। जबकि CAQM (सीएक्यूएम) ने इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं, हम मांग करते हैं कि केंद्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में संचालित होने वाली

बीएस III और बीएस IV बसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए। रिपोर्ट के मुताबिक, कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के औचक निरीक्षण के दौरान राय ने पाया कि आसपास के राज्यों से आने वाली सभी बसें बीएस 3 और बीएस 4 वाहन थीं। प्रदूषण दिल्ली के स्थानीय लोगों के लिए एक पुराना दुश्मन है और सर्दियों के महीनों के दौरान खास तौर पर बदतर हो जाता है। जहां उत्तर भारत के कई हिस्से हर साल जहरीली हवा की चपेट में आते हैं, वहीं देश की राजधानी सुखियां बंदोबस्त हैं और बार-बार आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता



है। इस साल, दिल्ली की आप सरकार ने कहा है कि दिल्ली प्रदूषण के स्रोत पर कोई अधिकारिक डेटा नहीं है। जबकि पिछले वर्षों में आप सरकार यह दावा करती रही है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाना दिल्ली में प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। पहले कांग्रेस पार्टी पंजाब में सत्ता में थी। फिर आप ने फरवरी 2022 का चुनाव जीता और अब पंजाब में उसकी सरकार है।



दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग के खिलाफ किया विशाल धरना प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने सोमवार, 30 अक्टूबर 2023 को 11 बजे विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया। क्योंकि दिल्ली सरकार और उसके दिल्ली परिवहन विभाग एवं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा प्रदूषण के नाम पर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की डीजल BS 4 बसों को 1 नवम्बर 2023 से दिल्ली में एंटी बेन करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। जंतर मंतर पर भारी संख्या में दिल्ली एनसीआर के बस वालों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और वहाँ उन्होंने CAQM और दिल्ली परिवहन विभाग की दमनकारी नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शन के बाद दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि माण्डल ने स्पेशल कमिश्नर श्री सहजद आलम जी मुलाकात करके अपना ज्ञापन भी उन्हें सौंपा।

ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने स्पेशल कमिश्नर से शिकायत करी की आप डीजल BS 4 को दिल्ली एनसीआर में बंद करके हजारों ट्रांसपोर्ट्स को बेरोजगार कर रहे हैं और लाखों परिवारों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। स्पेशल कमिश्नर ने हमारी बातों को ध्यान से सुना और कहा की अभी दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग सिर्फ दिल्ली एनसीआर में चलने वाली BS 4 डीजल बसें पूरी तरह बंद कर रहे हैं और 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत के डीजल BS 4 टैक्सी बसों को ये एनसीआर में बंद देंगे।

उन्होंने हमें राहत देते हुए कहा है की अगर आप अपनी BS 4 डीजल बसों को दिल्ली एनसीआर से लम्बी दूरी के लिए जाएंगे तो हम ऐसी बसों का चालान नहीं करेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की पूरे भारत के टैक्सी बस मालिक अभी हाल में ही 2 सालों से कोरोना महामारी से पीड़ित रह रहे हैं। दिल्ली सरकार एवं दिल्ली परिवहन विभाग और CAQM काफी समय से दुसरे राज्यों की सरकारी डिपो की परिवहन बसों को BS 6 डीजल या इलेक्ट्रिक या CNG गाड़ियों की एंटी के लिए दिल्ली में आने के लिए कह रहे थे। ये खबर भी हमें अखबारों के माध्यम से पता चलती रहती थी. दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का आर्डर आया है जिसमें BS 4 डीजल बसों की एंटी 1 नवम्बर 2023 से बंद करने के आर्डर कर दिए गए हैं।

वो भी सिर्फ राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जबकि पहले इन्होंने पूरे भारत की BS 4 डीजल बसों की एंटी दिल्ली में बैन की थी. शायद दुसरे राज्यों ने CAQM और दिल्ली सरकार से आगे के

लिए मोहलत मांग ली होंगी. क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट्स की भी काफी बसें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश नंबर की BS 4 डीजल बसें हैं उनको भी इन्होंने बस डिपो की तरह बंद करने का फरमान जारी कर दिया. लेकिन हमारी BS 4 डीजल बसें आल इंडिया टूरिस्ट परमिट है और इसका जिक्र अलग से दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने नहीं करा. जबकि इस से पहले एनसीआर दिल्ली की किसी भी ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन को इस बारे में ना ही बताया गया और ना ही CAQM या दिल्ली सरकार द्वारा की गई किसी मीटिंग में बुलाया गया.

संजय सम्राट का कहना है की पहले भी दिल्ली सरकार और कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा प्रदूषण के नाम पर डीजल से चलने वाली टूरिस्ट टैक्सी को पिछले साल भी ग्रेप लगाकर बंद किया गया, और उनपर 20 हजार तक जुर्माना भी किया गया.

ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की दिल्ली सरकार एवं उसका दिल्ली परिवहन विभाग और

CAQM वास्तव में प्रदूषण के नाम टूरिस्ट टैक्सी बसों के मालिकों को ही टारगेट कर रही है, और जान भुजकर हमारी डीजल BS 4 बसों की एंटी दिल्ली एनसीआर में बंद करना चाहते हैं जबकि हमारी डीजल BS 4 बसें आल इंडिया टूरिस्ट परमिट है जो ज्यादातर दिल्ली से ज्यादा दुसरे राज्यों में पर्यटकों को घूमाने ले जाती है।

पिछले साल भी इन्होंने 4 पहिये की डीजल BS 4 टैक्सी को बंद करा. लेकिन डीजल के ट्रक को खुले आम चलने की इजाजत दी. क्या डीजल की टैक्सी बसें पहिये के हिसाब से धुआँ देती हैं??? यें सोचने वाला सवाल है.

हमारे काफी ट्रांसपोर्ट्स ने 2019 के आखरी महीने में काफी डीजल की BS 4 बसें खरीदी अब 3 सालों में से 2 साल वें बसें पाकिंग में ही खड़ी रही थी, अब इन गाड़ियों का क्या होगा? इनकी किस्ते हम कहां से भरेंगे? डीजल टैक्सी बसें वें ही धुआँ अप्रैल महीने में देती है और वें धुआँ नवम्बर में, हमारी टैक्सी बसें सदी में कोई एकस्ट्रा धुआँ नहीं देती. ये प्रदूषण की समस्या पराली जलाने से और पटाखों की वजह से ज्यादा होता है, और सबसे बड़ी बात सर्दियों में मौसम बदलता ही है.

अभी भी जो ग्रेप सिस्टम इन्होंने बनाया है उसमें डीजल BS 4 की 4 पहियों की गाड़ियों को ग्रेप 3 में रखा है जब AQI 401 से 450 के बीच में होगा. लेकिन जो डीजल BS 4 के ट्रक हजारों की संख्या में रात को आते है दिल्ली एनसीआर में उनको ग्रेप 4 में



रखा है जब AQI 451 से ऊपर होगा. मतलब CAQM गाड़ी के पाहियों के हिसाब से प्रदूषण का पैमाना बना रहा है. ट्रांसपोर्ट से जुड़े धंधे में हजारों बसों के मालिक जुड़े है इनके लाखों ड्राइवर्स है और करोड़ों परिवार इस से जुड़े है. क्योंकि इसका चंडीगढ़, जम्मू, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की BS 4 डीजल बसों को आने की इजाजत क्यों दी गई है? सिर्फ इन 3 राज्यों की डीजल बसें धुआँ देगी और दुसरे राज्यों की बसें क्या

आँकसीज न देंगी? हमारे लोगो पर इतना पैसा नहीं है की BS 4 डीजल की गाड़ियों को बेचकर BS 6 डीजल की बसें खरीदे. सबसे बड़ी बात हम जो डीजल गाड़ियों में डाल रहे है वें भी BS 4 के हिसाब से ही मिल रहा है. जब डीजल एक जैसा है तो फिर BS 6 डीजल बस का क्या मतलब, वास्तव में थोड़ा बहुत डीजल गाड़ी में बदलाव करके बसों की कीमत 3 से 4 लाख बढ़ा दी जाती है और ये सारा खल BS सीरीज के नाम पर हो रहा है और कार और बसें बनाने वाली कम्पनी को भारी मुनाफा हो रहा है. ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने आज प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय ग्रह मंत्री, दिल्ली के उप राज्यपाल, दिल्ली

के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, से CAQM और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की शिकायत का ज्ञापन भी सौंपा. और इनसे मांग भी की CAQM और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को दोबारा से विचार करने को कहा जाए और हमारी BS 4 डीजल आल इंडिया टूरिस्ट परमिट टूरिस्ट बसों की जो लाइफ है उतना उन्हें चलने दिया जाए, क्योंकि ये भारत के करोड़ों लोगो की रोजी रोटी का सवाल है. और बसें बनाने वाली कम्पनी को भी अगर दिल्ली एनसीआर के BS 4 डीजल बसों के मालिकों को नाजायज चालान किये गए या तंग किया गया तो दिल्ली एनसीआर में बसों का चक्का जाम किया जायेगा।

advertisement Tariff

w.e.f. 1st January 2023

परिवहन विशेष

दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित तोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

| | Basic | 3rd Page | Back Page | Front Page Semi Sols | Front Page Sols |
|-----------------|-------------|----------|-----------|----------------------|-----------------|
| Delhi Aur Delhi | BW - Colour | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Delhi | 100* | 200* | 250* | 300 | 300 |

Special Instructions:-

- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- 3/W advertisement on page 3/Back will be charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Printers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- Colour charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाइन भुगतान सीधे बैंक खाते/फोन पे कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाइन भुगतान की रसीद क्वार्टर नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते हैं। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS* Account Name:-Transport Vishesh Limited IFSC CODE :- INDB0001396 Cur Account no :- 259212122095 या Phone pay :- 9212122095

मनीष सिंसोदिया को जमानत पर सुप्रीम इन्कार

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनीषों से जेल में कैद दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिंसोदिया को जमानत देने से इन्कार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा कि अगर 6 से 8 महीने में मुकदमा खत्म ना हो तो वह दोबारा जमानत की अर्जी लगा सकते हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित अनियमितता मामले में गिरफ्तार सिंसोदिया फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। दरअसल इस मामले में लगभग 20 से 30 हजार दस्तावेज हैं। और 290 से अधिक गवाह हैं। तब एस वी राजू ने कहा कि 9 से 12 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा। ज्ञात हो कि 16 अक्टूबर को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हम आम आदमी पार्टी को

भी आरोपित बनाने पर विचार कर रहे हैं। वकील मनु सिंघवी ने कहा कि नायर पार्टी का कार्यकर्ता था। और वह आतिशों और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। उन्होंने कहा कि सिंसोदिया 26 फरवरी से जेल में हैं। उधर ईडी ने कहा कि आबकारी नीति के लिए पडयंत्र रचा गया। पैसा लेकर छूट सुईया कराई गई। विजय नायर मनीष सिंसोदिया के इशारे पर काम कर रहा था। दरअसल 4 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा था कि जिस राजनीतिक पार्टी को कथित तौर फायदा पहुंचा, उसे आरोपित क्यों नहीं बनाया गया। सीबीआई ने अपने हलफनामों में मनीष सिंसोदिया की पत्नी की बिमारी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं है। उनका इलाज पिछले 23 साल से चल रहा है। ऐसे में यह भी उनके जमानत का आधार नहीं हो सकता।



सीएम अरविंद केजरीवाल को ED ने भेजा नोटिस, शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया



मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को समन भेजा है। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में दो नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि सीबीआई ने इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को समन भेजा है। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में दो नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि सीबीआई ने इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है।

ब्रज भूषण सिंह के वकील के तर्क पर सरकारी वकील ने दिया जवाब, कहा- आरोपी को जब भी मौका मिला, उसने छेड़छाड़ की

परिवहन विशेष न्यूज

महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली के कोर्ट में तर्क दिया। उनके वकील ने कहा कि चूंकि घटनाएं भारत से बाहर होने के आरोप हैं ऐसे में राजु एवैन्स कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। इसका लोक अभियोजक ने कड़ा विरोध किया। अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कोर्ट के क्षेत्राधिकार को दिए गए तर्कों का अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने विरोध किया। लोक अभियोजक ने कहा कि पीड़ितों के यौन उत्पीड़न का कार्य एक निरंतर अपराध था, क्योंकि यह किसी विशेष समय पर नहीं रुका था। लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी को

जब भी मौका मिलता था, उसने पीड़ितों के साथ छेड़छाड़ की। इस तरह के उत्पीड़न को अलग-अलग कोषकों में नहीं देखा जा सकता है। उत्पीड़न की श्रृंखला को एक कोषक के रूप में देखा जाना चाहिए।

एडिशनल मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने सुनवाई के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता और लोक अभियोजक को तीन सप्ताह में लिखित में दलील जमा करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

भारत से बाहर के अपराध की सुनवाई का अधिकार नहीं ब्रजभूषण की तरफ से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि राजु एवैन्स कोर्ट के पास भारत के बाहर कथित तौर पर किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि कथित अपराध टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की में हुए हैं। ऐसे में इस अदालत द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।



तीन राज्यों के चुनाव में तीसरा विकल्प बनने के प्रयास में 'आप', लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई खास रणनीति



विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों में से तीन में राष्ट्रीय दलों के बीच ही संघर्ष है। मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दशकों से बीजेपी-कांग्रेस के बीच लड़ाई रही है। यहां कोई अन्य विकल्प अभी तक बन नहीं पाया है। इस बार भी अबतक कोई तीसरा विकल्प नहीं दिख रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) ऐसे फसल की तलाश में है जिसे लोकसभा चुनाव के वक्त काटा जा सके।

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों में से तीन में दो बड़े राष्ट्रीय दलों के बीच ही संघर्ष है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दशकों से बीजेपी और कांग्रेस में ही हार-जीत का खेल होता रहा है। यहां कोई अन्य विकल्प अभी तक बन नहीं पाया है। इस बार भी अबतक तो कोई तीसरा विकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) ऐसे फसल की तलाश में है जिसे लोकसभा चुनाव के वक्त काटा जा सके।

दिल्ली मॉडल के सहारे पंजाब के बाद गुजरात में भी अच्छी उपस्थिति से उत्साहित अरविंद केजरीवाल तीनों राज्यों में आप को विस्तारित करने में लगे हैं। वैसे भी कांग्रेस की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि आईएनडीआई लोकसभा चुनाव के लिए है। ऐसे में कोई यह आरोप भी नहीं लगा सकता है कि आप या कोई तीसरा दल गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है। आम आदमी पार्टी की तैयारी बता रही है कि उसकी नजर भविष्य पर है।

तीन सौ से ज्यादा सीटों पर आप की लड़ने की तैयारी

हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों की कुल पांच सौ 20 विधानसभा सीटों में से करीब पौने दो सौ से अधिक सीटों पर 'आप' अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अभी तक आप ने मध्य प्रदेश में 69, राजस्थान में 63 और छत्तीसगढ़ में 57 प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। यह

सिलसिला थमा नहीं है। नामांकन की अंतिम तिथि तक तीनों राज्यों को मिलाकर तीन सौ से ज्यादा सीटों पर आप की लड़ने की तैयारी है।

विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश

अगर नतीजे अच्छे आ गए तो फिर पार्टी की तरफ से उसी आधार पर संसदीय चुनाव में सीटों की दावेदारी भी की जाएगी। चुनाव तो तेलंगाना और मिजोरम में भी हो रहा है, लेकिन केजरीवाल की प्राथमिकता इन तीन राज्यों पर ही है। इसका कारण है कि तीनों राज्यों का राजनीतिक और सामाजिक चरित्र हिंदी पट्टी के ऐसे राज्यों से मिलता-जुलता है, जहां की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है।

क्षेत्रीय दलों को स्थान नहीं मिल पाया है हालांकि, लंबे प्रयासों के बावजूद क्षेत्रीय दलों को स्थान नहीं मिल पाया है। केजरीवाल को यह भी पता है कि बिहार-यूपी की तरह उक्त तीनों राज्यों में जाति आधारित राजनीति खूब होती है। इसलिए आप की प्राथमिकताओं में वैसे युवा और निष्पक्ष वोटर हैं, जो आने वाली नई सरकार से शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की अपेक्षा रखते हैं। साथ ही जाति-धर्म से हटकर सोचते हैं। हाल के वर्षों में ऐसे वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है।

दिल्ली मॉडल से कद बढ़ाने की कोशिश दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक अपना मॉडल बनाया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मुफ्त योजनाओं का पिटाया है। इसी मॉडल को आम आदमी पार्टी चुनाव वाले राज्यों में प्रचारित कर अपना कद बढ़ाने का प्रयास करती है। कांग्रेस की गारंटियों में भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। मुफ्त योजनाओं की भरमर्ष है। हाल के कुछ वर्षों में आप चुनाव नतीजों का निष्कर्ष है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस शासित राज्यों में ही अपनी जगह बनाई है। गुजरात में भी उसने कांग्रेस का कद ही छोटा किया है।

चंडीगढ़ से दिल्ली लौटनी थी बरात, एंबुलेंस से आए तीन शव; बच्चे से लेकर बूढ़ों तक...सबकी आंखे नम

चंडीगढ़ से दिल्ली के नंद नगरी बरात की जगह तीन शव आए। सोनीपत में हुए सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। यह सुनते ही सब दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था जो युवा हंसते हुए बारात में जा रहे थे वापसी में घर पर उनके शव आएंगे।

पूर्वी दिल्ली। नंद नगरी ई ब्लॉक में सोमवार को मातम छाया रहा। चंडीगढ़ से नंद नगरी बरात की जगह तीन शव आए, जिस वक्त शव एंबुलेंस से नंद नगरी पहुंचे तो बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सड़क पर आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। किसी ने नहीं सोचा था जो युवा हंसते हुए बारात में जा रहे थे, वापसी में घर पर उनके शव आएंगे।

खुशियां मातम में बदलीं शहीदों की खुशियां मातम में बदल गईं। नंद नगरी निवासी नाजिम नाम के शख्स की बारात रविवार सुबह सात बजे चंडीगढ़ गई थी। दो बस व कारों में बरात गई थी। दुल्हा का भाई आजम अपने चचेरे भाई दिलशाद, दूर के रिश्तेदार जैद, जाकिर, नदीम के साथ सुबह दस बजे चंडीगढ़ के लिए गया था। बस ने कार को मारी टक्कर



पांचों ई ब्लॉक में रहते थे और घर आसपास ही है। शाम सात बजे बारात वापस लौट रही थी। नाजिम ने बताया कि हादसे के वक्त दिलशाद कार चला रहा था, जबकि आजम अगली सीट पर बैठ आया था। दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। बरात में शामिल वहां नों में काफी दूरियां थी। रात दो बजे हरियाणा पुलिस का कॉल आया कि एक कार को बस ने टक्कर मार दी है। हादसे में चार की मौत, एक घायल चार लोगों की मौत हुई है और एक घायल

है। यह सुनते ही सब दंग रह गए। रास्ते से बरात को सोनीपत के अस्पताल लेकर गए। सोमवार को उनके भाई आजम का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। बाकी तीन लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद नंद नगरी के कब्रिस्तान में सुपुर्द एंखाक कर दिए हैं। आजम अपने भाई की शहीदों को लेकर काफी उत्साहित था। मंगलवार दोपहर को उसके भाई का वलीमा था। एकसाथ चार मौत की वजह से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। आजम विश्वास नगर इलाके में ग्रीस की

फैक्ट्री में नौकरी करता था। हादसे में जान गंवाने वाले जैद उर्फ फैजल का कबाड़ का कारोबार था। हफ्तेवार में पिता शौकीन अली, मां रेशमा, पत्नी और दो बच्चे हैं। इसके परिवार के सदस्य भी बरात में शामिल थे। लेकिन वह सब बस में थे। नदीम घर के पास ही परचून की दुकान चलाते थे। इनके परिवार में पिता सलीम, मां नाजमा और दो बड़े भाई हैं। जाकिर का कपड़े रंगाई का काम था। उनके परिवार में पिता अंसार अहमद, मां और दो बहनें हैं।

वायुसेना के इंजीनियरों ने मात्र 1.5 करोड़ में तैयार कर दिया बोइंग विमान का रडार, US कंपनी ने मांगे थे 20 गुना ज्यादा पैसे

साहिबबाद। बोइंग-737-200 विमान के रडार को बदलने के लिए अमेरिकी कंपनी ने 30 करोड़ रुपये मांगे थे। वन बेस रिपेयर डिपो (1 बीआरडी) और भारतीय वायु सेना के इंजीनियरों ने इस पर अध्ययन किया। महज 1.3 करोड़ रुपये में मौसम रडार बनने के बाद उसे बदल दिया। इसे बनाने से ज्यादा विमान में लगाना मुश्किल था। दुनिया भर में इस तरह के केवल 40 बोइंग विमान हैं। विमान के मौसम रडार की विफलता के कारण इसके संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। आवश्यक पुर्जे उपलब्ध नहीं होने के कारण मौसम रडार का रखरखाव इंजीनियरों के लिए कठिन हो गया था। अमेरिकी कंपनी ने मांगे थे 30 करोड़ रुपये

मौसम रडार में दिक्कत आने के बाद उसे बदलवाने के लिए अमेरिकी बोइंग कंपनी ने 30

करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसके बाद भारतीय वायु सेना ने एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और राकवेल कंपनी के साथ 7.38 करोड़ रुपये में इसे बदलवाने का अनुबंध किया। 181 फ्लाइंग, वायु सेना और वन बीआरडी ने बोइंग में मौसम रडार बदलने का अध्ययन शुरू किया। पांच माह में रडार को बदलने में सफलता हासिल की, जिसके बाद आरसीएमए से रडार लगाने की मंजूरी मिल गई। रडार बदलने के बाद विमान की क्षमता बढ़ गई है। पूर्व में मौसम रडार लगा होने के कारण मानसून और विपरीत मौसम में मिशन को पूरा करने में विमान को 79 प्रतिशत सफलता मिल रही थी।

मुश्किल था मौसम रडार लगाना रडार बदलने के बाद मिशन को पूरा करने में सफलता दर 91 प्रतिशत हो गई है। वायु सेना

आकादमी हैदराबाद के इंजीनियरों ने बताया कि मौसम रडार को बनाने से मुश्किल था इसे विमान में लगाना। रडार लगाने में सफलता मिलना बड़ी उपलब्धि है। बोइंग विमान एक विशाल व्यावसायिक विमान है, जिसे भारत ने अमेरिका से खरीदा था। यह बोइंग विमान अमेरिका की बोइंग कंपनी इसका मेटेनेंस करने की मोटी रकम वसूल करती थी। अब भारत में ही इसका मेटेनेंस किया जा रहा है। अब विदेश पर इसके मेटेनेंस की निर्भरता खत्म हो गई है। आने वाले समय में भारत में बोइंग जैसे विमान बनाए जाएंगे।

बोइंग-737-200 विमान की मौसम रडार को लगाने में भारत ने सफलता हासिल की है। इसे महज 1.3 करोड़ रुपये में बदल दिया गया। - नंदी इंद्रनील, विंग कमांडर, भारतीय वायु सेना।



वन बेस रिपेयर डिपो (1 बीआरडी) और भारतीय वायु सेना के इंजीनियरों ने बड़ी सफलता हासिल की है। इंजीनियरों ने बोइंग-737-200 विमान के रडार को बदलने का अध्ययन किया और महज 1.3 करोड़ रुपये में मौसम रडार बनने के बाद उसे बदल दिया। वहीं अमेरिकी कंपनी ने इसी काम के लिए 30 करोड़ रुपये मांगे थे।

चुनौतियों के बीच आशावादी आर्थिकी



डा. जयंती लाल भंडारी

निःसंदेह यद्यपि भारत में डिजिटलीकरण और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा निर्माण में काफी प्रगति की है, मगर इस समय कारोबारी माहौल और निवेशकों के विश्वास को बेहतर बनाने के लिए और अधिक संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। भारत नए वैश्विक आर्थिक अवसरों को मुट्टियों में लेते हुए दिखाई देगा।

इन दिनों जब दुनिया इजराइल-हमास युद्ध, बढ़ती तेल कीमतों और गिरती वैश्विक विकास दर की चुनौतियों का सामना कर रही है, तब विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संवैधानों और रिपोर्टों में भारत की आर्थिकी की आशावादी तस्वीर उभरकर आना सुकूनदेह है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के उपभोक्ताओं और कारोबारों के विचारों का जो सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, उसके निष्कर्षों में कारोबारी और वित्तीय विचार भारत में व्यापक तौर पर आर्थिक विस्तार को लेकर आशाजनक रुख दिखाते हैं। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में खुदरा मंहगाई में कमी आ रही है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है, बेरोजगारी में कमी आई है, कर राजस्व में सुधार हुआ है। जहां रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं स्वरोजगार को अपनाते वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। बैंक ऋण में अच्छी वृद्धि के मद्देनजर सबसे अधिक वृद्धि खुदरा और व्यक्तिगत ऋण में हुई है। इस सर्वेक्षण से संकेत मिल रहा है कि देश में उपभोक्ताओं के विचारों की नकारात्मकता कम हो रही है और अधिक से अधिक उपभोक्ता भविष्य में आमदनी बढ़ने के मामले में आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। भारतीय उपभोक्ताओं के आशावादी होने का एक बड़ा कारण एक ओर भारत को रूस से कम मूल्यों पर कच्चे तेल की आपूर्ति होना है, वहीं भारत के द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाई जाना भी है। पहले हम 27 देशों से कच्चे तेल का आयात करते थे, वहीं अब 39 देशों से कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं। इस तरह अर्थव्यवस्था की समग्र तस्वीर व्यापक तौर पर आशावादी नजर आ रही है। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट 2023 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की आशावादी तस्वीर प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में पहला वैश्विक विकास दर 3 फीसदी रहेगी, वहीं भारत की विकास दर 6.3 फीसदी रहेगी। साथ ही भारत दुनिया में सबसे तेज विकास दर वाला देश है। इसी तरह पिछले दिनों 3 अक्टूबर को विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट-2023 में भी कहा गया कि चालू वित्त वर्ष में निवेश और मांग के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल भारत की विकास दर जी-20 देशों के बीच दूसरे स्थान पर है और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में

औसतन लगभग दोगुनी है। इस ऊंची विकास दर की वजह मजबूत आर्थिक मांग, मजबूत सार्वजनिक बुनियादी ढांचा निवेश और मजबूत वित्तीय क्षेत्र है। विश्व बैंक की तरह दुनिया की प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की तेज विकास दर के अनुमान प्रस्तुत किए हैं। एसएंडपी ने 6.6 फीसदी और फिच, एडीबी और आईसीडी ने 6.3 फीसदी के अनुमान लगाए हैं। इसी तरह रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.5 फीसदी रहने की संभावना है। चूंकि अमेरिका और रूस के साथ-साथ दुनिया के अधिकांश देशों के द्वारा भारत के साथ लगातार आर्थिक मित्रता के कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे में भारत की सबसे ज्यादा विकास दर के साथ वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के लिए वैश्विक आर्थिक अवसर भी बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस वर्ष 2023 में जी-20 देशों की सफल अध्यक्षता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज विकास की नई संभावनाएं निर्मित हुई हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक सफल आयोजन से जहां दुनिया में भारत की डिजिटल आर्थिक मजबूत हुई है, वहीं भारत की नई डिजिटल पूंजी भारत की आर्थिक ताकत बनते हुए दिखाई दे रही है। अब भारत जी-20 देशों के साथ-साथ दुनिया के कई अन्य देशों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) विकसित करने की नई भूमिका में है। दुनिया के आठ देशों में अपने यहां डीपीआई के विकास के लिए भारत से समझौते किए हैं। जी-20 से जहां भारत की विकासशील देशों, ग्लोबल साउथ के देशों और अफ्रीकी देशों के लिए और महत्वपूर्ण बना है,

यह भी महत्वपूर्ण है कि जी-20 से भारत के वैश्विक व्यापार, भारत से निर्यात, भारत में विदेशी निवेश, भारत में विदेशी पर्यटन और भारत के डिजिटल विकास का नया क्षितिज सामने आया है। जी-20 से दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के मद्देनजर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। जहां 55 देशों के प्राकृतिक संपदा संपन्न अफ्रीकी संघ पटल पर अपनी कूटनीति का दबदबा बढ़ाया, वहीं चीन के आर्थिक प्रभुत्व वाले अफ्रीकी संघ के देशों में भारत ने चीन का रास्ता रोकने की जोरदार पहल भी की है। अब भारत अफ्रीकी देशों में कृषि, स्वास्थ्य, फार्मासी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा व ढांचागत विकास के क्षेत्र में तेजी से कदम आगे बढ़ाएगा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जी-20 में घोषित हुए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कारिडोर (आईएमईसी) के माध्यम से रेल एवं जल मार्ग से भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसरों का ऐसा ढेर लगाया जा सकेगा, जिससे चीन की तुलना में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ जाएगी। वस्तुतः आईएमईसी चीन के बीआरओ प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा जवाब भी है। अब आईएमईसी के तहत भारत से पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप तक कारिडोर बनेगा और रेल लाइनें बिछेंगी। एक दूसरे के ऊर्जा और रेल जर्मनी साझेदार देश होंगे। भविष्य में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को यूरोप और पश्चिम एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला एक अहम माध्यम बनेगा। जी-20 ने भारत में विदेशी पर्यटन की संभावनाओं के लिए

अभूतपूर्व नया अध्याय भी लिखा है। निश्चित रूप से वर्तमान इजरायल-हमास संकट और बढ़ते कच्चे तेल के मूल्यों के बीच भारत के लिए वैश्विक आर्थिक अवसरों के बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वैश्विक अवसरों को मुट्टी में लेने के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा। चीन में मंदी और चाइना प्लस वन की रणनीति का लाभ लेने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस समय भी चीन अगले कई दशकों के सबसे अहम कारोबारों के लिहाज से सर्वाधिक अनुकूल स्थिति में है। ऐसे में दुनिया का नया अपूर्णतक देश बनने के लिए भारत को अभूतपूर्व रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। जहां भारत को दुनिया के नए वैश्विक अपूर्णतक और अफ्रीकी संघ में नए प्रभावी नियंत्रण की भूमिका को मुट्टी में लेना होगा, वहीं अभी से भारत को मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक कारिडोर के तेज क्रियान्वयन के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। यद्यपि भारत राजकोषीय रूप से अनुशासित रहा है और देश के केंद्रीय बैंक ने भी मंहगाई को कम करने के लिए तेजी से काम किया है, लेकिन अब मंहगाई नियंत्रण पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है। निःसंदेह भारत के द्वारा यद्यपि भारत ने डिजिटलीकरण और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा निर्माण में काफी प्रगति की है, मगर इस समय कारोबारी माहौल और निवेशकों के विश्वास को बेहतर बनाने के लिए और अधिक संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। हम उम्मीद करें कि ऐसे रणनीतिक प्रयासों से भारत इजराइल-हमास युद्ध और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों से निर्मित चुनौतियों के बीच नए वैश्विक आर्थिक अवसरों को मुट्टियों में लेते हुए दिखाई देगा।

संपादक की कलम से

चुनाव आयोग की सक्रियता

भारत के चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को 'कारण बताओ नोटिस' भेजने में देरी नहीं की। आयोग ने उन रथी यात्राओं को भी रोक दिया है, जिनमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 'रथ-प्रभारी' बनने और भारत सरकार की परियोजनाओं का प्रचार करने को बाध्य करने का संकुलन तक जारी किया जा चुका था। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी दौरान बयान दिया कि सीबीआई और इंडी 'कुत्ते की तरह' घूमती रहती हैं। प्रियंका और नोटिस भेजकर उनका स्पष्टीकरण नहीं मांगा अथवा अब भी नोटिस की कार्रवाई विचारधीन है? बहरहाल आयोग ने कांग्रेस और बाजपा के दोनों स्टार नेताओं के बयानों को 'आदर्श आचार संहिता' के खिलाफ माना है। प्रियंका ने राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा था कि उन्होंने एक मंदिर की दीवार-पट्टी में 21 रुपए ही लिफाफे में रखकर डाले थे। दरअसल ऐसे तंज पर वोट नहीं मिला करते। प्रधानमंत्री का ऐसा सार्वजनिक अपमान चुनावी मुद्दा भी नहीं है और न ही जनता इसे स्वीकार करती है। जिस तरह अन्य राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने मुद्दों पर जनादेश हासिल करने को प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस महासचिव को भी मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए था। यह मानसिकता ही 'सामंतवादी' है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी छत्तीसगढ़ के एक मंत्री पर जो टिप्पणी की थी, वह भी आचार संहिता का उल्लंघन करती थी। हिमंता तो संवैधानिक पद पर आसीन हैं, लिहाजा उनसे शब्दों और भाषा की मर्यादा की अधिक अपेक्षाएं हैं। यकीनन चुनाव आयोग की 'तुरंत कार्रवाई' उल्लेखनीय और प्रशंसनीय है, लेकिन 5 दिसंबर को पांच राज्यों में चुनाव-प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यदि तब तक इन नेताओं के संतोषजनक स्पष्टीकरण आयोग तक नहीं पहुंचते हैं, तो इन नेताओं पर क्या कार्रवाई की जा सकेगी, यह तलाश और सरोकार का सवाल है। शायद इसीलिए कई संदर्भों में चुनाव आयोग को 'दंतहीन' माना गया है। चुनाव तो गुजर जाएंगे, नेताओं को जो बयान देने थे, वे दे चुके हैं, लिहाजा सियासत खेली जा चुकी है, लेकिन आचार संहिता के संरक्षण को लेकर आयोग की भूमिका क्या है? हालांकि असम के मुख्यमंत्री ने 'एक्स' (टि्वटर) पर लिखकर अपने बयान का स्पष्टीकरण दिया है और छत्तीसगढ़ की कार्रवाई को ही 'दोषी' करार दिया है। प्रियंका गांधी ने अपना पक्ष रखने के लिए व्हाट्सएप चैनल का इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना हट्टी तीव्र और नाशक बातचीत करती झगडाऊ मुद्दा ही बना रहता है।

संवैधानिक स्पष्टीकरण के लिए सोशल मीडिया कोई उचित मंच नहीं है। उसकी वैधानिकता भी नहीं है। यह ऐसा मंच है, जहां राजनीतिज्ञों का मानना है कि वे आयोग के नोटिस और स्पष्टीकरण को नजरअंदाज कर सकते हैं। दरअसल वे भी दंडनीय होना चाहिए, लिहाजा चुनाव आयोग में सुधारों की बात की जाती रही है। मान लीजिए, किसी भी नेता ने आचार संहिता के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात कही, तो उसे त्वरित कार्रवाई के तहत प्रचार करने और भाषण देने से 'अयोग्य' करार दे देना चाहिए। अंतिम निर्णय नोटिस के जवाब के बाद दिया जा सकता है। यह विशेषाधिकार संसद और भारत सरकार ही दे सकती हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के विचार जारी हैं, लिहाजा प्रचार का धुआंधार और उग्र होना स्वाभाविक है।

राय पानी में कितनी दरारें

हिमाचल सरकार की शिकायत पर 'पानी में दरार' ढूँढ़ने आया केंद्रीय वल। भारी बरसात में इस बार बड़े-बड़े बांधों ने अपनी करतूत को इस कदम घातक बनाया कि जख्म लिए हिमाचल की तस्वीर बता रही हुई है गुनाह कैसे-कैसे। पाँच व पंडोह डैम के अलावा मलाणा-2 तथा पार्वती-3 विद्युत परियोजना के बांधों में बरती गई कोलाही ने परेशानियाँ ही नहीं बढ़ाई, बल्कि हिमाचल में आई आपदा को विकरालता का सबब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हैरानी कि वह केवल दो परियोजनाओं कोल बांध व नाथपा झाकड़ी परियोजना में ही अली वॉनिंग सिस्टम लगाया गया था, जबकि अन्य स्थानों पर ऐसे निर्देश का पालन नहीं हुआ। बांध सुरक्षा में अपनाई गई लापरवाही ने सैन जवाग को ही निगल लिया, जबकि पाँच बांध से बिना तैयारी छोड़े गए पानी ने मंड क्षेत्र में तबाही मचा दी थी। मंडी शहर के डूबते मंदिरों तक आ पहुँचा नदी का उफान बताता रहा कि पंडोह बांध ने कब-कब गुस्ताखी की। ये तमाम परियोजनाएँ हिमाचल के सामाजिक परिदृश्य के खिलाफ खड़ी हैं और जनता की कोलाही के रूप में यह रखवाली करती है कि कहीं बांध का गुस्ता न फूट पड़े। दरअसल बांध हिमाचल के पानी को पूरी क्षमता से खींचने की पद्धति में निशानदेही करते रहे हैं। उनके लक्ष्य हिमाचली जिंदगी के विपरीत पानी की सरहद बनाते हैं। ये हमारी मजबूरियाँ क्यों बन गई कि आपदा के हिस्से का सारा पानी हिमाचल का, बाढ़ प्रदेश की और काम अन्य राज्यों का। सुकून की जिंदगी छीन चुके बांध, अब नमक हलाली में उस फुन की शिनाख्त है, जो हिमाचल को बेडियाँ पहना कर मजाक उड़ा रहा है। बीबीएमबी एक जीता जागता उदाहरण है जो प्रदेश के अधिकारों की तोहीन करता है। वाटर सेस की झलक मात्र से बीबीएमबी के पार्टनर राज्यों का रवैया बताता है कि पानी को बांधने वाले सिर्फ हीराना चाहते हैं कि हिमाचल बंधक बना रहे। यह कैसा नियम और कैसा राष्ट्रीय फलक, जो बांधों को निचोड़ने के बावजूद यह नहीं देखता कि राष्ट्र निर्माण की ये ईंट अपने बगल में छुरी छुपा के कहीं वार कर रही है। इस बार की अधिकार के वाटर सेस पर उन राज्यों को बचा दिया कि विकास का शौतान कहां-कहां छुपा था। वह बादल बन कर आया जरूर, मगर बांध और विद्युत परियोजनाओं उसे बांधने के बजाय तबाही के लिए खुला छोड़ दिया। वे बांध को लंबालब करने के बाद बरसाती हवाओं का रुख मोड़ते हैं, वे धुरंधर है इसलिए पानी खींच कर बाढ़ हमें छोड़ते हैं। यही नहीं इस बार तो पानी-पानी में बैर उभर आया। हिमाचल का पानी हिमाचल में 13 हजार करोड़ की बर्बादी करता है, तो यह राष्ट्रीय क्षति नहीं, लेकिन यही बहते हुए जब पड़ोसी राज्यों में पहुंचता है तो दर्द का एहसास बदल जाता है। मौसम पर तो किसी का वश नहीं, लेकिन पानी के रुख पर राष्ट्र के जज्बत बहकने नहीं चाहिए। हिमाचल का फर्ज केवल बांध को पानी से लंबालब करना नहीं और अगर यही करार है, तो सारी बारिश को खरोद के बताओ कि बादलों का मुकम्मल होना केवल बरसना नहीं, मिलजुल कर मौसम को बांटना होता है। बहरहाल वर्षों बाद उस दरखास्त पर केंद्र का दिल आया, जिसमें निकले हैं पहाड़ के आंसू। बांधों की शरारत के अंदाज में ही, तो राष्ट्र को मालूम होगा कि हिमाचल की बर्बादी में लिपटे तेरह हजार करोड़ के निशान कैसे बांट जा सकते हैं। इस पानी से जुड़े अधिकार से वाटर सेस पर उन राज्यों की मक्कारी दर्ज होती है, जो पंजाब पुनर्गठन की भावना को केवल अपने हित में देखते हैं। शानन बांध परियोजना की समाप्त हो रही लीज और बीबीएमबी से जुड़ी हिमाचल की आर्थिक संभावना की भी पड़ताल होनी चाहिए।

शव संवाद-16

शिकायत की सार्वभौमिकता, राष्ट्रवाद से भी ऊपर है, क्योंकि विश्व की कई शिकायतों में आपसी भाईचारा सरहदों को पिछला देता है। मच्छर की शिकायत रूके हुए पानी और थमे हुए इन्सान से है और इस तरह की प्रजाति हर समाज और समाज के हर देश से है। लोगों को अपने-अपने खुदा से शिकायत रहती है, फिर भी दूसरे के धर्म को अच्छा नहीं मानते। घर में परिवार की शिकायत, परिवार को पड़ोस से शिकायत, पड़ोसी को पड़ोसी के धन से शिकायत, धन को आयकर से शिकायत, आयकर विभाग को लोगों की जेब से शिकायत और इसी जेब से निकल रहे नेताओं से देश को शिकायत। शिकायतें भी घूम-फिर कर लौट आती हैं। जिन शिकायतों के कारण हम सरकारें तक बदल देते हैं, वही लौट कर हमारे ही आंगन में लेट जाती हैं। हर किसी को लगता है कि उसी को

शिकायत ईमानदार है, लेकिन शिकायत तो शिकायत है, अनादि काल से शुरू हुई और अनंत तक जारी रहेगी। यही सोचने-सोचते बुद्धिजीवी हर रात को सुबह और सुबह को रात में बदलते देखता आ रहा है। हर शिकायत को वाजिब ठहरा कर भी एक बुद्धिजीवी ही है जिसकी शिकायत बेअसर हो रही थी। आज वह रात भर नहीं सोया। वैसे बुद्धिजीवी सोया ही कब। जागता रहा और सोचता रहा कि उसकी जागरूकता ही देश और समाज को बचा रही है, जबकि स्थिति उलट है। देश में किसी के पास कोई शिकायत नहीं। देश इसीलिए चल रहा है क्योंकि लोगों ने शिकायत करनी छोड़ दी है। खैर बुद्धिजीवी को शिकायत यह थी कि मोहल्ले में गायत्री मंत्र जाप ने उसके कान में सुर्खियाँ घुमा दी थीं। उसकी रातें मोहल्ले के गायत्री मंत्र जाप से बेचैन हैं। उसी से उसका धर्म कहां रहा था कि

पड़ोसी के ऊंचे स्पीकर में खलल न डाले और लोकतांत्रिक अधिकार कह रहा था कि जाकर इस गला कड़ा प्रदर्शन की शिकायत करे। वह आज तय कर चुका था कि देश के लिए इस अशांति से लड़ना। वह आगे बढ़ ही रहा था कि गली में टोकर खाकर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी जेब से कई आधी-अधूरी, कई पूरी-पूरी और कई लाचार शिकायतें गिर गईं। इससे पहले कि वह इन्हें उठाता, सोचने लगा कि उसे गिरने से शिकायत है या गिरने के कारण से। गायत्री मंत्र के जाप के साथ-साथ अब कहीं से अज्ञान का वक्त उस सताने लगा। इन्होंने शिकायतों ने उससे नई शिकायत करके पूछ डाला, 'शिकायत यह है कि वह जिंदा क्यों है और जिंदा है तो शिकायत क्यों है।' बुद्धिजीवी ने आदतन अपनी ही शिकायत से पल्ला झाड़ने की कोशिश की और फिर से उठ खड़ा हुआ। सोचने लगा, 'हर

व्यक्ति होश में आते ही सर्वप्रथम शिकायत करना तो सीखता है। बच्चों-बच्चों में अंतर इसीलिए है क्योंकि कोई मां की गोद में सीखता, तो कोई बाप के रौब में सीखता है।' बहरहाल आज मन में आई शिकायत ने उसके घुटने छील दिए थे। गली में बिखरी शिकायतों को समेट कर वह अस्पताल पहुंचता था। वहां भी हर मरीज जीने की दुआएं मांग रहा था। शोर ही शोर, चारों ओर शोर। ध्वनियों का कोलाहल। उसने उस दिन अस्पताल के हर कोने पर शिकायत देखी और सोचा कि ये डाक्टर तो हर मरीज की अपने ही जिस्म की शिकायत सुन कर कैसे खामोश रहते हैं। उसने तय किया कि आईदा वह भी अपने देश की शिकायतें सुन कर खामोश ही रहेगा। शिकायतों के खिलाफ हृदय परिवर्तन करके के धायलों को अस्पताल लाते हुए देख कर वह टिठक गया। धायल रो रहे थे, अपने दौड़ रहे थे। अस्पताल यह देखकर भी रूटीन में जुटा था। अस्पताल की व्यवस्था में यह भी नार्मल था कि उसके देखते-देखते कुछ धायल मरकर शव में परिवर्तित हो चुके थे। बुद्धिजीवी ठहर सागया। उसे अब यह नहीं सूझ रहा था कि वह सड़क दुर्घटना की शिकायत करे या अस्पताल तक पहुंच कर धायलों के मरने की शिकायत करे। उन्हीं लाशों के बीच उसने भी अपनी तमाम शिकायतें रख दीं। देश में लोग इसी तरह हर रोज बिना कारण मरते हैं और फिर शव के साथ जनता के हजारे प्रश्न और शिकायतें जल जाती हैं। उस दिन बुद्धिजीवी ने बिना शमशानघाट गए अपनी शिकायतों को अस्पताल आकर दुर्घटना में मारें गए लोगों के साथ जला दिया। -क्रमशः

निर्मल असो

विचार भारत में ओलंपिक की संभावनाएं व चुनौतियां

भारत को 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास करने ही चाहिए। यह प्रयास शहरी और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और विशेष रूप से आर्थिक गतिविधि और पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा एथलेटिक उत्कृष्टता में भारत की सहभागिता को बढ़ाएगा। यह विस्तृत योजना बनाने की जरूरत है कि खेलों को कहां आयोजित किया जाए

आयोजन कभी नहीं हुआ। भारत ने भी ओलंपिक में एक अग्रदूत के रूप में रुचि व्यक्त की है, हालांकि 2036 के लिए मेजबान शहर को चुनने में समय लगेगा। ब्रिस्बेन को 2032 संस्करण के लिए जुलाई 2021 में ही चुना गया था। इससे पहले कि हम भारत की संभावनाओं पर विचार करें, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कदम भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को उजागर करता है। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सज्जस्तता की इच्छा हो या जी-20 की अध्यक्षता को लेकर उत्साह, भारत ने लगातार अंतरराष्ट्रीय मंच पर सीट की मांग की है। ओलंपिक मेजबानी का टैग हमारे देश को बदलती विश्व व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान दे सकता है। पदक जीतने में देश की हालिया सफलता इसकी जनसंख्या या आर्थिक विकास के अनुपात में नहीं है। ओलंपिक की मेजबानी से भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिल सकता है। भारत ने हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 107 पदक लेकर शानदार प्रदर्शन किया है। जब से अभिनव बिंद्रा ने ऑलंपिक 2008 में देश का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीता है, तब से अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। देशवासियों को यह विश्वास भी है कि भारत को 2024 में पेरिस में दोहरे अंकों में पदक जीतेगा। ओलंपिक जैसे मेगा आयोजन एक बड़ी चुनौती भी साथ लेकर आते हैं। उदाहरण के तौर पर रियो 2016 और टोक्यो 2020 दोनों आयोजनों की दौरान भयंकर सार्वजनिक आक्रोश देखा गया था। टोक्यो के मामले में, कहा गया था कि वित्तीय बोझ बढ़कर 15.4 बिलियन डॉलर हो गया था, जो प्रारंभिक अनुमान से दोगुने से भी अधिक था। हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई राज्य विकटोरिया ने बढ़ते खर्च



के कारण 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हाथ खींच लिया और कनाडाई प्रांत अल्बर्टा ने 2030 संस्करण के लिए अपना नाम वापस ले लिया। चीन ने 2008 में खेलों की मेजबानी पर 50 अरब डॉलर खर्च किए थे। प्रमुख खेल अर्थशास्त्री एंड्रयू जिम्बालिस्ट ने कहा है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अरबों डॉलर के खैल आयोजन की मेजबानी करना कठिन होगा। ओलंपिक समिति उन स्थानों को चुनकर खेलों की मेजबानी को और अधिक टिकाऊ बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पहले से ही अधिकांश बुनियादी ढांचे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, पेरिस में लगभग 95 फीसदी बुनियादी ढांचे पहले से ही अस्तित्व में हैं। लॉस एंजिल्स में, जहां 2028 खेल आयोजित

होंगे, उन्हें एक भी नया खेल स्थल नहीं बनाना पड़ा। भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपनी आकांक्षाओं को अंतर्निहित जटिलताओं के साथ कैसे जोड़ता है। जब भारत ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, उस समय खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल थे। गिल ओलंपिक की मेजबानी की कोशिश के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए भारी रकम खर्च करने को कोई मतलब नहीं है। भारी वित्तीय निवेश, एक शहर में उन्नत बुनियादी ढांचे और यहां तक कि मौसम की स्थिति जैसी कई चुनौतियों के साथ ओलंपिक की मेजबानी करना भारत के लिए एक आदर्श लक्ष्य है। वर्तमान में हमारे पास चाहे कई ओलंपिक स्तर की सुविधाएं नहीं हैं, पर फिर भी शीघ्र गतिमान होना

बुनियादी ढांचे का विकास भारत के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब भारतीय शहर का नाम नहीं बताया जो ओलंपिक की मेजबानी करने का प्रयास करेगा, लेकिन कई विशेषज्ञों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो शहर अहमदाबाद हो सकता है। अगस्त 2023 में, गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात ओलंपिक क्लॉनिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर यूपीआर लिमिटेड के नाम से ओलंपिक योजना के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन की शुरुआत की थी। भारत ने अतीत में कभी भी ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है, लेकिन देश ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। उस समय, नई दिल्ली मेजबान शहर था। यदि ओलंपिक 2036 के लिए भारत की दावेदारी अहमदाबाद के साथ आगे बढ़ती है, तो शहर को खेल स्थलों, प्रशिक्षण सुविधाओं, एथलीटों के लिए आवासीय पार्क आदि सहित खेल के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश करना होगा। भारत को 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास करने ही चाहिए। यह प्रयास शहरी और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और विशेष रूप से आर्थिक गतिविधि और पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा एथलेटिक उत्कृष्टता में भारत की सहभागिता को बढ़ाएगा। इस बात पर विस्तृत योजना बनाने की जरूरत है कि खेलों को कहां आयोजित किया जाए। आयोजन के लिए बनाए गए आवासीय, कार्यालयों और खेल सुविधाओं को भारत के बुनियादी ढांचे में कैसे एकीकृत किया जाए। कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर यह कहा जा सकता है कि अगर भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करता है तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी बड़ी कामयाबी होगी। प्रत्युष शर्मा

दिवाली पर कंपनी, दोस्त या रिश्तेदार से मिलता है गिफ्ट? जानिए कितना देना होगा टैक्स

परिवहन विशेष न्यूज

यदि आपको मिला उपहार कर छूट की श्रेणी में नहीं आता है तो आप पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2) के तहत कर लगेगा। दिवाली के दौरान कंपनियां अपने कर्मचारियों से लेकर दोस्तों तक को उपहार देती हैं। रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार आदि को तोहफा देते हैं। जानिए आपको इन पर कितना टैक्स देना होगा।

नई दिल्ली। नवंबर के दूसरे हफ्ते में रौशनी का त्योहार दिवाली आने वाली है। इस दौरान मिठाईयों के साथ-साथ लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। अगर आपको मिलने वाला गिफ्ट छूट की श्रेणी में नहीं आता तो आपको उसपर आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 56(2) के तहत टैक्स देना होता है। दिवाली के दौरान कंपनियां अपने कर्मचारियों से लेकर दोस्त, एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार, आदि, को गिफ्ट देते हैं। ऐसे में आपको गिफ्ट से जुड़े टैक्स के नियम पता होने चाहिए।

नियोक्ता से मिलने वाले गिफ्ट
अगर नियोक्ता द्वारा सालाना 5000 रुपये तक का गिफ्ट दिया जाता है तो उसपर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि अगर 5000 की रकम से अधिक का गिफ्ट होती है तो उस उपहार को 'अनुलाभ' (perquisites) माना जाता है और उस हिस्से पर टैक्स लगाया जाता है।

रिश्तेदार से मिलने वाले गिफ्ट
आयकर विभाग ने रिश्तेदार की परिभाषा तय की है। 'रिश्तेदार' का अर्थ व्यक्ति का जीवनसाथी है, व्यक्ति का भाई या बहन; व्यक्ति के पति/पत्नी का भाई या बहन; व्यक्ति के माता-पिता में से किसी एक का भाई या बहन; व्यक्ति का कोई भी वंशानुगत लगन या वंशज; व्यक्ति के पति/पत्नी का कोई वंशानुगत लगन या वंशज; और उनके जीवनसाथी। अगर इनके द्वारा आपको उपहार दिया जाता है तो उस गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

दोस्तों से मिलने वाले गिफ्ट
आयकर विभाग दोस्तों से मिलने वाले गिफ्ट को आपके आय के साथ जोड़ता है और उसपर टैक्स लगाता है। हालांकि यह टैक्स तब लगाया जाता है जब गिफ्ट की कीमत एक साल में 50,000 रुपये से अधिक होती है। अगर कीमत सालाना 50 हजार रुपये से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। इसके अलावा शादी के दौरान मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है।

अडानी ग्रीन एनर्जी का नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में पहुंचा 370 करोड़ के पार, कंपनी ने जारी किए आंकड़ें

Adani Green Energy की कुल आय बढ़कर 2589 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 1684 करोड़ रुपये हुआ करती थी। इस अवधि के दौरान ऊर्जा की बिक्री एक साल पहले की तिमाही में 3067 एमयू से बढ़कर 5737 मिलियन यूनिट (एमयू) हो गई है। आइए इससे संबंधित पूरी डिटेल के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Adani Green Energy ने सोमवार को जुलाई-सितंबर तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में लगभग 149 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो एक साल पहले की तुलना में 371 करोड़ रुपये थी। ऐसा मुख्य रूप से कंपनी की हाई सेल के वजह से हो पाया है। कंपनी की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 149 करोड़ रुपये था। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

रिपोर्टिंग क्वार्टर में Adani Green

Energy की कुल आय बढ़कर 2,589 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,684 करोड़ रुपये थी। इस अवधि के दौरान ऊर्जा की बिक्री एक साल पहले की तिमाही में 3,067 एमयू से बढ़कर 5,737 मिलियन यूनिट (एमयू) हो गई है। वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2023) में ऊर्जा की बिक्री 78 प्रतिशत सालाना (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर 11,760 एमयू हो गई है, जो मुख्य रूप से सौर, पवन और हाइड्रोजन पोर्टफोलियो में मजबूत क्षमता वृद्धि और बेहतर सीयूप (क्षमता उपयोग कारक) द्वारा समर्थित है।

कंपनी का बयान
इस संबंध में कंपनी ने कहा कि गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा आरई बलस्टर बनाने के हमारे अगले मील के पथर की खोज में, हमने पहले ही 5,000 से अधिक कार्यबल तैनात कर दिया है। खावड़ा में हम सबसे कुशल 5.2 मेगावाट पवन टरबाइन में से एक सबसे उन्नत TOPCon सौर मॉड्यूल के साथ-साथ भारत के सबसे बड़े और स्थापित कर रहे हैं।



अडानी ग्रीन एनर्जी के सीईओ अमित सिंह ने कहा कि ये प्रयास हमें ऊर्जा की न्यूनतम स्तर की लागत प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करेंगे।

भारत स्थित अडानी समूह का एक हिस्सा अडानी ग्रीन एनर्जी के पास परिवहन, निर्माणधीन और सम्मानित परियोजनाओं

सहित 20.4 गीगावाट के समग्र लॉक-इन पोर्टफोलियो के साथ सबसे बड़े वैश्विक नवीकरणीय पोर्टफोलियो में से एक है।

फेस्टिव सीजन में एसबीआई अपने ग्राहकों को दे रहा है ये खास ऑफर, CIBIL स्कोर से लेकर लोन पर मिल रही है बंपर छूट

परिवहन विशेष न्यूज

फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन में जहां एक त्योहार की धूम मची थी वहीं दूसरी तरफ इस धूम पर चार चांद लगाने के लिए कई बैंक अपने ग्राहकों को स्पेशल ऑफर देते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने भी अपने ग्राहकों को लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के ऑफर दे रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। देखते-देखते 2023 का सबसे बड़ा फेस्टिव सीजन आ गया है। इस फेस्टिव सीजन जहां एक तरफ त्योहार की धूम होती है तो उसी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई तरह के ऑफर व डिस्काउंट का मौसम भी होता है।

इस मौसम में चार चांद लगाने के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने ग्राहकों को के लुभाने वाले ऑफर और डिस्काउंट लेकर आया है। हाल में ही दशहरा उत्सव गया है और लोग दिवाली का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे फेस्टिव सीजन एसबीआई ग्राहकों को कौन-से खास ऑफर और



डिस्काउंट मिल रहे हैं? इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे।

एसबीआई होम लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को होम लोन

(Home Loan) पर रियायत दे रहा है। इसको लेकर बैंक ने जानकारी दी है कि वह होम लोन में 65 बीपीएस तक की कमी कर सकता है। यह जानकारी स्टेट बैंक ने अपने अधिकारिक वेबसाइट पर दी है। बैंक के वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार यह ऑफर 31 दिसंबर 2023 तक वैध है।

बैंक ने इस ऑफर को लेकर जानकारी दी है कि इस ऑफर को सिबिल स्कोर से जोड़ दिया गया है। सिबिल स्कोर जितना अधिक होगा ग्राहकों को उतनी ज्यादा रियायती दरों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ग्राहक को होम लोन टेकओवर या फिर रेडी-टू-मूव ऑफ़ेशन में अतिरिक्त 20 बीपीएस का डिस्काउंट मिलेगा। यह डिस्काउंट केवल उन ग्राहकों को मिलेगा जिनका सिबिल स्कोर 700 अंक के पार होता है।

एसबीआई क्रेडिट कार्ड
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड पर भी ऑफर दिया जा रहा है। बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के ऑफर पेश किये हैं। यह ऑफर मोबाइल फोन, लैपटॉप, फैशन, फर्नीचर, ज्वेलरी आदि पर दी जा रही है। इसके अलावा ईएमआई पर भी ऑफर दिया जा रहा है। बैंक ने कई ब्रांड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के बाद अब ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते समय अतिरिक्त डिस्काउंट और कैशबैक का लाभ मिलता है। यह फेस्टिव ऑफर 15 नवंबर 2023 तक वैध रहेगा।

करवाचौथ पर पत्नी को दें ये खास गिफ्ट, इन तोहफों से मजबूत होगी पत्नी की फाइनेंशियल स्टेटस

करवा चौथ का त्योहार आ रहा है। ऐसे में आप कंप्यूज होंगे कि आप अपने पत्नी को क्या तोहफा दें। अगर आप बाकी की तरह साड़ी हैंडबैग फ्लावर बुके आदि देने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस से अच्छा है कि आप अपनी पत्नी को कुछ ऐसा गिफ्ट दें जो आपकी पत्नी को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करेगा।

नई दिल्ली। 11 नवंबर 2023 को करवा चौथ है। इस त्योहार में पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। ऐसे अगर आप भी अपनी पत्नी के लिए कोई खास गिफ्ट खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपने भी इंटरनेट पर सर्च कर रहे होंगे। इसके अलावा आप साड़ी, हैंडबैग, फ्लावर बुके, चॉकलेट्स, मेकअप किट आदि देने की सोच रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि इस बार आप अपनी पत्नी को कुछ अलग गिफ्ट दें। आपको कोई ऐसा तोहफा देना चाहिए जो अलग भी हो और काम का भी। ऐसे में आप अपनी पत्नी के लिए फाइनेंस से जुड़े कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को क्या फाइनेंशियल गिफ्ट दे सकते हैं।

SIP या म्यूचुअल फंड
आप अपनी पत्नी के लिए SIP गिफ्ट कर सकते हैं। दरअसल, आज भी महिलाएं घर के डिब्बे में पैसे रखती हैं। यह पैसे बचाने का सबसे लोकप्रिय और पुराना तरीका है जो महिलाओं द्वारा अपनाया जाता है। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी को

एक एसआईपी अकाउंट गिफ्ट करते हैं तो यह आपकी पत्नी को सेविंग करने और अच्छे रिटर्न देने में काफी मदद करेगा।

ऐसे में आप इस करवाचौथ अपनी पत्नी के लिए म्यूचुअल फंड का SIP अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें निवेश करने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। एसआईपी में आपको सेविंग अकाउंट या एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है।
हेल्थ इश्योरेंस
हेल्थ इश्योरेंस आज के समय में बहुत जरूरी होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 महिलाओं में से सिर्फ 20 महिला के पास हेल्थ इश्योरेंस होता है। अगर आपकी पत्नी अभी तक हेल्थ इश्योरेंस में कवर नहीं है तो आप उन्हें हेल्थ इश्योरेंस गिफ्ट कर सकते हैं। यह उनके लाइफ की सुरक्षा करने में काफी मदद करेगी। इसके अलावा यह मेडिकल खर्चों को कम करने में भी मदद करेगा।

गोल्ड
महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद गोल्ड होता है। आप अपनी पत्नी को फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड भी गिफ्ट कर सकते हैं। यह सुरक्षित होता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड करना पसंद नहीं करते हैं तब आप फिजिकल गोल्ड की कोई ज्वेलरी या फिर सिक्के गिफ्ट कर सकते हैं। यह गिफ्ट आपकी पत्नी को बहुत पसंद आएगा। इसलिए गोल्ड को एवरग्रीन तोहफा कहा जाता है। वहीं, भारतीय संस्कृति में गोल्ड गिफ्ट करना काफी शुभ माना जाता है।

लिस्ट होगा जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर का शेयर, 37 गुना हुआ था सब्सक्राइब

JSW Infra IPO का शेयर 3 अक्टूबर को लिस्ट होगा IT+2 टाइमलाइन में लिस्ट होने वाला ये दूसरा आईपीओ होगा। इससे पहले केवल आरआर काबेल का ही आईपीओ T+2 टाइमलाइन पर लिस्ट हुआ है। एसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक खुला था। इसका इश्यू साइज 2800 करोड़ रुपये का था और ये पूरा फ्रेश इश्यू था।

नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर का शेयर मंगलवार (3 अक्टूबर, 2023) को लिस्ट हो सकता है। T+2 टाइमलाइन में लिस्ट होने वाला ये दूसरा आईपीओ होगा। इससे पहले केवल आरआर काबेल का ही आईपीओ T+2 टाइमलाइन पर लिस्ट हुआ है। बता दें, बाजार नियामक सेबी की ओर से एक सितंबर से आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए T+3 टाइमलाइन को ऐच्छिक रूप से लागू किया गया है। यह नया नियम एक दिसंबर, 2023 से आईपीओ लाने वाली सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा।

JSW Infra IPO 37 गुना भरा
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक खुला था। आईपीओ का अलॉटमेंट 28 सितंबर को फाइनल हुआ था। ये 2800 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू 37.37 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल निवेशकों के लिए तय किया गया कोटा 10.32 गुना सब्सक्राइब हुआ था। व्हाईबी के लिए निर्धारित कोटा 57.09 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एनआईआई के लिए रिजर्व कोटा 15.99 गुना सब्सक्राइब हुआ था। जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर की खास बात यह है कि ये पूरा फ्रेश इश्यू है। यानी आईपीओ में मिलने वाला सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 113 रुपये से लेकर 119 रुपये तय किया गया था। इसका लॉट साइज 126 शेयरों का है। जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, क्रेडिट सुइस सिन्डिकेटीज (इंडिया), डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, एचएसबीसी सिन्डिकेटीज एंड कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिन्डिकेटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। वहीं, कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ रजिस्ट्रार हैं।

डीमैट अकाउंट में चुटकियों में ऑनलाइन भरें नॉमिनी, फॉलो करें ये प्रोसेस

डीमैट अकाउंट में नॉमिनी दर्ज करना सेबी की ओर से अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 31 दिसंबर 2023 के बाद आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। डीमैट खाताधारक के परिवार का सदस्य दोस्त या उससे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति भी नॉमिनी हो सकता है। आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी अपने डीमैट खाते में दर्ज कर सकते हैं।

नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) की ओर से सभी डीमैट खातों में 31 दिसंबर, 2023 तक नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि अगर डीमैट खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्तियों को आसानी से उसकी संपत्ति पर अधिकार मिल सके।

किन खाताधारकों को नॉमिनी भरना अनिवार्य?
वे डीमैट खाताधारक जिनके पास अपना व्यक्ति डीमैट अकाउंट ने उन सभी लोगों के लिए नॉमिनी भरना आवश्यक है। संयुक्त डीमैट खाताधारक भी नॉमिनी भर सकते हैं। हालांकि, गैर-व्यक्तिगत खातों में नॉमिनी भरना संभव नहीं है।

कौन हो सकता है नॉमिनी?
डीमैट खाताधारक के परिवार का सदस्य, दोस्त या उससे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति भी नॉमिनी हो सकता है। आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट में संपत्ति में अनुपात तय करना होगा।
नॉमिनेशन प्रोसेस
नॉमिनेशन फॉर्म आसानी से आप अपनी डीपी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) से या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने डीमैट अकाउंट का नंबर और निजी जानकारी देनी होगी। साथ ही डीमैट खाताधारक को उसका व्यक्ति का नाम, उससे रिश्ता, जन्मतिथि और पता आदि बताना होगा, जिसे वह नॉमिनी बनाना चाहता है। वहीं, अगर नॉमिनी एक से ज्यादा है तो संपत्ति में उनका अनुपात भी तय कर सकते हैं।

ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे भरें?
आप आसानी से डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनेशन भर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। फिर डीमैट अकाउंट में आपका नॉमिनी दर्ज हो जाएगा।

आंध्र-ओडिशा सीमा पर भीषण रेल दुर्घटना: 45 ट्रेनें रद्द, 22 का मार्ग बदला

मनोरंजन सासमल, ओडिशा

भुवनेश्वर : आंध्र-ओडिशा सीमा पर हुए भीषण ट्रेन हादसे के कारण रेलवे विभाग ने 45 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इसी तरह, 22 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है और 11 को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। जाहिर है कि 6 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है।

रद्द की गई ट्रेनों में पुरी-शालीमार और शालीमार-पुरी एक्सप्रेस, पलासा-विशाखापटना स्पेशल ट्रेन, विशाखापटना-कोरबा ट्रेन, कोरबा-विशाखापटना ट्रेन, पलासा-विशाखापटना स्पेशल ट्रेन, विशाखापटना-पारादीप एक्सप्रेस, पारादीप-विशाखापटना एक्सप्रेस, रायगड़ा-विशाखापटना पैसेंजर शामिल हैं। विजयनगरम-विशाखापटना स्पेशल ट्रेन, विशाखापटना-गुनापुर स्पेशल ट्रेन, गुनापुर-विशाखापटना स्पेशल ट्रेन, एमजीआर चेंनई सेंट्रल-पुरी एक्सप्रेस, विशाखापटना-कोरबा एक्सप्रेस, विशाखापटना-पारादीप एक्सप्रेस, रायगड़ा-गुंटूर एक्सप्रेस, विशाखापटना-प्लासा पैसेंजर, प्लासा-शबीखापटना पैसेंजर, विशाखापटना-तिरुपति पैसेंजर, तिरुपति-विशाखापटना पैसेंजर, ब्रह्मपुर-विशाखापटना एक्सप्रेस, विशाखापटना-ब्रह्मपुर एक्सप्रेस, भुवनेश्वर-विशाखापटना इंटरसिटी और विशाखापटना-भुवनेश्वर इंटरसिटी आदि।



सांसों पर 'जहरीला' संकट: ठंड आते ही बढ़े 30 फीसदी सांस के रोगी, जानें इसके चार लक्षण और बचाव के पांच तरीके

दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे प्रदूषण के चलते एम्स शाखा की ओपीडी में सांस और दमे के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य रोग विशेषज्ञ के पास हर रोज 50 से 60 मरीज सांस रोग के आ रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि सर्दियों के आते ही लगभग 30 प्रतिशत मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। एम्स शाखा की ओपीडी में प्रतिदिन करीब तीन हजार मरीज उपचार करवाने के लिए आते हैं। इनमें से 250 मरीज सामान्य रोग विशेषज्ञ के पास बुखार, खांसी और सांस का उपचार करवाने के लिए आ रहे हैं। एम्स शाखा के सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश ने बताया कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से उनकी ओपीडी में सांस रोगी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उनकी ओपीडी में हर रोज 50 से 60 मरीज सांस रोगी के आ रहे हैं। जिनकी उम्र 50 से ऊपर है।

बढ़ते प्रदूषण की वजह से उन मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि पहले सांस रोगी मरीज पंप का इस्तेमाल काफी कम किया करते थे लेकिन अब मरीजों को बार-बार कर रहे हैं। राजीव कॉलोनी निवासी घनश्याम ने बताया कि उनकी सांस की परेशानी पहले से थी लेकिन अब प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से उनकी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी वजह से वह

अब सुबह व शाम को सैर करने के लिए भी घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार वह अब दिन में दो बार पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं।

सर्दियों में बढ़ जाते हैं 30 प्रतिशत मरीज

ब्रीके अस्पताल के सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉ. मोहित अग्रवाल ने बताया कि काला दमा व अस्थमा, मरीजों के लिए प्रदूषण और कम तापमान खतरनाक होता है। अन्य माह की अपेक्षा सर्दियों के चार महीनों (नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी) में अस्पतालों में इनकी संख्या 30 फीसदी तक बढ़ जाती है।

यह है लक्षण

- तेजी से सांस लेना।
- बलगम के साथ खांसी आना।
- सीने में इंफेक्शन व जकड़न होना।

- कमजोरी आ जाना
- इन सावधानियों को बरतें
- मरीजों को हमेशा गर्म कपड़े पहनने चाहिए
- बाहर निकलने पर नाक और मुंह को कवर जरूर करें
- अस्थमा और काला दमा पीड़ितों के कमरे में अंदर धूपबत्ती न जलाएं।
- घरों में अंगीठी, हीटर आदि के प्रदूषण से मरीज को बचाएं।
- मरीज के लिए सप्ताह में तीन से चार बार 45-45 मिनट के लिए व्यायाम बेहद आवश्यक है।

चुनावी प्याज भाव से फिर बरपा राजनीतिक खेल

परिवहन विशेष | एसडी सेठी।

5 राज्यों के चुनावी भाव ने प्याज पर फिर राजनीतिक खेल शुरू कर वोटों के ऑप्शनिकाल दिए हैं। दो दिन पहले तक 20 से 25 के बेभाव में बिकने वाली प्याज के एक किलो 120 से 150 रुपये किलो तक पहुंचने से वोटों की आंखों में पानी लाने का खेल चल रहा है। इससे पहले टमाटर छलांग लगा रहा था। एक जमाने में टमाटर के 40 रुपये किलो तक की ऊंचाई से भाजपा को दिल्ली की सत्ता गवाह पडी थी।

दरअसल 5 विधान सभाओं के चुनावों के मद्देनजर जमाखोरी ने कृत्रिम प्याज की कमी और बड़ी कीमतों से बेजार वोटों के मिजाज में तीखा पन ला दिया है। इससे जनता तो परेशान है ही, सत्तारूढ़ दल के नेता भी बेहाल हैं। जबकि विपक्ष गदगद है। दरअसल विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते तक प्याज 25-30 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध था लेकिन महज दो दिनों में ही बढ़कर 100 रुपये से 140 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बेहिसाब प्याज कीमत में उछाल के पीछे मुख्य कारण में प्याज की जमाखोरी है। जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई और कीमतें ऐन चुनाव के वकत ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं। प्याज व्यापारियों ने जमाखोरी को सेफगाई पहनाकर आम उपभोक्ता को ही प्याज के आखरी स्टॉक को जमा करना बता रहे हैं। इससे कमी पैदा हो रही है। और कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की वकालत की है। उनका कहना है कि अगर सरकार लागू करना नहीं लगाए तो प्याज की कीमत 150



प्याज की कालाबाजारी पर कार्रवाई होगी

रूपये किलों को भी टाप सकती है। उधर केंद्र सरकार ने भी प्याज निर्यात मूल्य यानि (एम्ईपी) लगाया है। यह प्रतिबंध 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। वहीं व्यापारियों का कहना है कि प्याज की नई फसल दिवाली के बाद नवंबर के आखरी सप्ताह तक बाजारों में आ जाएगी। मगर जब तक उनका कहना है कि अगर सरकार लागू करना नहीं लगाए तो प्याज की कीमत 150

मनोरंजन सासमल, ओडिशा, भुवनेश्वर: प्याज की हो रही है कालाबाजारी, रहें सावधान। विभागीय मंत्री ने जिला प्रशासन को प्याज की कालाबाजारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। गरीबों और मध्यम वर्ग को रसोई के गलीचों पर एक महंगा तमाचा। प्रदेश में 70 टॉप प्याज रेट हालांकि, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शिफारिशों को सही कीमत पर प्याज दिलाने पर जोर दिया है। विभागीय मंत्री अतनु सव्यसाची नायक ने जिला प्रशासन को प्याज की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जैसे-जैसे प्याज की फसल का समय नजदीक आएगा, अंतर को प्रबंधित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कैपर सही कीमत पर कैसे मिले, इस पर जोर दिया जा रहा है।

दिल्ली की हवा सबसे दूषित, चार जगह AQI 400 पार

एनसीआर में दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। दिल्ली की हवा समग्र रूप से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। कम्बोवेश यही स्थिति पूरे सप्ताह तक बने रहने का अनुमान है।

राजधानी में मौसम बदलने व हवा की गति कम होने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। देशभर के 221 शहरों में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) छठे स्थान पर रहा। अक्टूबर में एनसीआर के मुकाबले पहली बार दिल्ली में सोमवार को हवा बेहद खराब रही। यहाँ एक्यूआई 347 दर्ज किया गया, जोकि रविवार के मुकाबले 27 सूचकांक अधिक रहा। यह इस सीजन का सबसे अधिक एक्यूआई रहा। सुबह एक्यूआई 333 दर्ज किया गया, वहीं दोपहर तक यह औसतन 340 हो गया। वहीं, वजीरपुर व रोहिणी समेत चार इलाकों में हवा गंभीर और 29 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी पहुंच गई।

एनसीआर में दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। दिल्ली की हवा समग्र रूप से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। कम्बोवेश यही स्थिति पूरे सप्ताह तक बने रहने का अनुमान है। दीपावली से पहले ही दिल्ली धीरे-धीरे गैस चैंबर की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में पराली व वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं चूल रहा है। ऐसे में हवा की गति कम होने से

प्रदूषण के कण हवा में उठ रहे हैं, जिससे हवा प्रदूषित हो रही है। अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहती है, तो ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया जा सकता है।

221 शहरों में दिल्ली छठे स्थान पर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, देशभर के 221 शहरों में दिल्ली की हवा छठे स्थान पर सबसे अधिक प्रदूषित रही। इसमें हनुमानगढ़ में एक्यूआई 428 दर्ज किया गया, जोकि गंभीर श्रेणी में रहा। वहीं, जौड़ में 416, बठिंडा में 381, श्री गंगानगर में 368 व बहादुरगढ़ में 362 एक्यूआई दर्ज किया गया।

वजीरपुर व रोहिणी सबसे अधिक प्रदूषित

सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को 29 इलाकों में बेहद खराब हवा दर्ज की गई। इसमें वजीरपुर में 429, रोहिणी में 425, मुंडका में 417 व नॉर्थकैम्पस में 401 एक्यूआई दर्ज किया गया, जोकि गंभीर श्रेणी है। सोनिया विहार में 397, पंजाबी बाग में 392, बवाना में 390, जहांगीरपुरी में 389, आनंद विहार में 385, ओखला फेज-2 व न्यू मोती बाग में 378, अशोक विहार में 375, नरेला में 355, द्वारका सेक्टर-8 में 343 व बुराड़ी क्रॉसिंग में 370 समेत 29 इलाकों में एक्यूआई दर्ज किया गया। आया नगर में 286, लोधी रोड में 297 व पूसा में 278 वायु सूचकांक दर्ज किया गया, जोकि खराब श्रेणी है।

दो गुटों की मारपीट में एक व्यक्ति की मौत, दो लोग घायल

दिल्ली के नंगली सकरावती इलाके में एक गोदाम में दो गुटों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दो अन्य लोग घायल भी गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति को चोरी के लिए गोदाम में घुसने के संदेह में एक वहां मौजूद कर्मचारियों ने पकड़ लिया था।

नई दिल्ली। नंगली सकरावती इलाके में एक गोदाम में दो गुटों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दो अन्य लोग घायल भी गए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना रविवार की रात को हुई थी, जिसमें धर्मेन्द्र (33) की मौत हुई है।

अस्पताल में कर्मचारी ने तोड़ा दम
सोमवार को पुलिस ने जानकारी दी कि दिल्ली के एक गोदाम में दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें तीन लोगों को चोट आई। इसके बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक फैक्ट्री कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। दो अन्य लोगों का इलाज चल रहा है।

चोरी के संदेह में व्यक्ति को पकड़ा
पुलिस के मुताबिक, एक व्यक्ति को चोरी के लिए गोदाम में घुसने के संदेह में एक वहां मौजूद कर्मचारियों ने पकड़ लिया था। कुछ समय बाद एक और गुट आ गया और आरोप लगाया कि उस व्यक्ति को पीटा जा रहा है। इसी के साथ गोदाम के कर्मचारियों के साथ झगड़ा किया, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

दो आरोपी हिरासत में लिए गए
पुलिस ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस स्टेशन नजफगढ़ में आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच चल रही है।

आंध्रा ट्रेन एक्सीडेंट : ट्रेन हादसे पर सीएम केजरीवाल ने जताया दुख, बोले- देश में बार-बार दुर्घटनाएं होना चिंताजनक

परिवहन विशेष न्यूज

Andhra Pradesh Train Accident: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि बीते दिन आंध्र प्रदेश में हुआ ट्रेन दुर्घटना बेहद दुखद है। मृतक के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में दो ट्रेनों की टक्कर में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है। मृतक के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

अरविंद केजरीवाल ने ट्रेन हादसे को बताया बेहद दुखद

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि बीते दिन आंध्र प्रदेश में हुआ ट्रेन दुर्घटना बेहद दुखद है। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनी को खो दिया। उनके साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग घायल हुए हैं, वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। देश में बार-बार इस तरह की ट्रेन दुर्घटनाओं का होना बेहद चिंताजनक है।

आंध्र प्रदेश में हुई ये ट्रेन दुर्घटना बेहद दुखद है। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनी को खो दिया उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग

घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। देश में बार-बार इस तरह की ट्रेन दुर्घटनाओं का होना बेहद चिंताजनक है। <https://t.co/DoGttWFlg>
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 29, 2023
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जताया शोक
वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से भी बयान जारी किया गया। बयान में पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। उन्होंने अलामां डा और कांतकपल्ले खंड के बीच दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन दुर्घटना के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजन को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार की रुपये की आर्थिक मदद का एलान किया गया।

रेल मंत्री ने किया मुआवजे का एलान
जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि हावड़ा-चेन्नई रूट पर विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम-रायगढ़ा पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर हो गई। हादसे में तीन कोच क्षतिग्रस्त हुए हैं। बचाव अभियान जारी है। सहायता और



एम्बुलेंस के लिए स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ को सूचित किया गया है। दुर्घटना राहत ट्रेनें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। हादसे की वजह से अब तक कुल 18 ट्रेनें रद्द हुई हैं और 22 ट्रेनों का रूट बदला गया है। रेल

मंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को ढाई लाख रुपये और सामान्य रूप से घायल लोगों के लिए 50 हजार रुपये के मुआवजे का एलान किया है।

छात्रा कीर्ति को ऑटो से खींचने वाला मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर, हमले में युवती की हो गई थी मौत

छात्रा पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी जितेंद्र पर 12 से ज्यादा लूट के मामले और एक गैंगस्टर का मुकदमा भी था। छात्रा से लूट के मामले में फरार होने के बाद उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

गाजियाबाद में लूट के लिए ऑटो से इंजीनियरिंग की छात्रा को खींचने वाले मुख्य आरोपी और पुलिस के बीच सामंजस्य सुबह मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी जितेंद्र मारा गया है। जानकारी के अनुसार, सोमवार तड़के करीब पांच बजे मसूरी क्षेत्र में नहर पट्टी पर पुलिस और लूटरे के बीच मुठभेड़ हुई। जितेंद्र पर 12 से ज्यादा लूट के मामले और एक गैंगस्टर का मुकदमा भी था। छात्रा से लूट के मामले में फरार होने के बाद उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

दरअसल, एनएच-9 पर उद्योग कुंज के पास लूटरे के हमले में घायल हुई इंजीनियरिंग की छात्रा कीर्ति (19) की उपचार के दौरान रविवार की शाम मौत हो गई थी। बाइक सवार लूटरे ने मोबाइल फोन

लूटने के लिए उसे ऑटो से खींचने का प्रयास किया था। सड़क पर गिर जाने से उसके सिर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टरों ने उसका आप्रेशन किया था, लेकिन जान नहीं बच सकी। हापुड़ के पन्नापुरी निवासी रविंद्र की बेटी और गाजियाबाद के एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष की दोनहार छात्रा कीर्ति के साथ घटना 27 अक्टूबर की शाम करीब साढ़े चार बजे हुई थी।

वह सहेली दीक्षा के साथ घर जा रही थी। पीछा करते आ रहे बाइक सवार दो बदमाशों ने उससे मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया। उसने विरोध किया तो उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींच दिया। वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। मोबाइल फोन बदमाश के हाथ में आ गया। बदमाश मोबाइल लूटकर भाग गए थे। सहेली और ऑटो चालक ने कीर्ति को अस्पताल में भर्ती कराया था। उसे पहले पिलखुवा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां से गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल भेजा गया। वहां रविवार की शाम उसने दम तोड़ दिया।